

एक नजर

सीएम ने दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संस्था पर जारी अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा बुद्ध का अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश सम्पूर्ण मानवता के लिए अमूल्य निधि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा हम सभी को जीवन में धर्म का आचरण करने, नैतिक मूल्यों और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करती है। महात्मा बुद्ध ने विश्व कल्याण के लिए मैत्री भावना तथा बिना किसी भेदभाव के संगठित रहने पर बल दिया। मानव मात्र के लिए उनके संदेश सदैव ही प्रासंगिक बने रहेंगे।

राहुल गांधी ने फिर कहा-सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना बंद करेंगे

चंडीगढ़, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के जवानों को मजदूरों की तरह बना दिया है। सेना अग्निवीर योजना नहीं चाहती है। यह पीएमओ द्वारा बनाई गई योजना है। एक बार कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम इस योजना को पूरी तरह से रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा, भाजपा का कहना है कि शहीदों को रद्द कर देंगे (एक सामान्य जवान और अधिकारी) जिन्हें पेंशन, शहीदों का दर्जा और सभी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी तरफ गरीब परिवार का व्यक्ति जिसे अग्निवीर नाम दिया गया है। अग्निवीरों को न शहीद का दर्जा मिलेगा, न पेंशन, न केंद्र की सुविधा राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा का युवा सेना में चयनित होने पर गर्व महसूस करता है इसका अलावा राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर भी बयान दिया उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान दिन भर खेतों में काम करते हैं। मोदी सरकार ने आपके अधिकार छीन लिए और अरबपतियों की मदद के लिए भूमि न्यायाधिकरण विधेयक को खत्म कर दिया। फिर तीन कृषि कानून आए, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया उन्होंने आगे कहा कि चार जून को जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। जहां तक कृषि ऋण माफी का सवाल है, हम 'कर्ज माफी' आयोग लाएंगे। बता दें कि हरियाणा की दस लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा।

सातवें चरण में 57 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 904 उम्मीदवार

नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण में 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि 1 जून को होने वाले मतदान का यह सातवां चरण इस लोकसभा चुनाव की वोटिंग का अंतिम चरण है। इसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती प्रारंभ होगी।

सातवें चरण की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण में 57 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 2105 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। सभी 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए चरण 7 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई, 2024 थी। दाखिल किए गए सभी नामांकनों की जांच के बाद 954 नामांकन वैध पाए गए। नाम वापसी के बाद अंतिम रूप से चुनावी मैदान में 904 उम्मीदवार शेष बचे हैं।

चुनाव आयोग ने बताया कि चरण 7 में पंजाब में 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 598 नामांकन फॉर्म थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 13 संसदीय क्षेत्रों से 495 नामांकन थे। बिहार के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से सर्वाधिक 73 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। इसके बाद दूसरे नंबर पर पंजाब के लुधियाना संसदीय क्षेत्र से 70 नामांकन पत्र प्राप्त हुए।

चुनाव आयोग के मुताबिक 7वें चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 16 है। सातवें एवं आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा।

ममता सरकार को बड़ा झटका

कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द किए 2010 के बाद जारी 5 लाख में ओबीसी सर्टिफिकेट

कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। उसके कार्यकाल में जारी करीब पांच लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि इस संख्या में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का भी है। बुधवार को जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर को खंडपीठ ने कहा कि 2011 से किसी मानक नियम का पालन किए बिना ही राज्य में ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि इस तरह ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह माने बिना जारी किए गए हैं, इसलिए उन सभी प्रमाण पत्रों को रद्द किया जाता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस कालखंड के दौरान जारी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वालों की नौकरी बरकरार रहेगी। मई 2011 में पश्चिम



बंगाल की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह दावा करती रही हैं कि उनकी सरकार ने लगभग सभी मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में ला दिया है और मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी इस आशय का लाभ उठा रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने बार-बार इस दोहराया है लेकिन अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने 2011 के बाद से जिस प्रक्रिया के तहत ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं, वह अवैध था। हाई कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की सूची पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार ही तैयार की जानी चाहिए। सूची में केवल उन्हीं जातियों को शामिल किया जा सकता है जो 2010 तक ओबीसी समुदाय से तात्त्विक रखते थे।

दून में डॉक्टरों की एसीआर-वेतन अटकाया, पीजी विवाद में फैसले का इंतजार

देहरादून। दून मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का आलम है। डॉक्टरों के प्रमोशन के लिए एसीआर यानि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उनके विभागों से ही अटका दी गई है। जेआर वेतन, प्रशिक्षु स्टैंडिंग को तसे हैं। पीजी डॉक्टरों के बीच नेत्र रोग विभाग में विवाद में कमेटी की बैठक नहीं हो पा रही है। जबकि विभाग में गुटबाजी अभी भी हावी है।



पीजी डॉक्टरों के विवाद में टली बैठक, बढ़ा इंतजार
दून मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में पीजी डॉक्टरों में विवाद के लिए बनी कमेटी की मंगलवार को बैठक नहीं हो सकी। दोनों पक्ष बैठक के संबंध में पूछताछ एवं इंतजार करते रहे। बाद में पता चला कि कमेटी के सदस्य पूरे उपलब्ध नहीं है। विभाग में पीजी डॉक्टरों में विवाद सामने आया था। दो पक्षों ने एक दूसरे पर उपोद्गन एवं मानसिक शोषण का आरोप लगा पीजी सेक्शन, प्राचार्य को शिकावत की थी। एचओडी मामले को नहीं सुलझा पाई थी। प्राचार्य ने छह सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसमें विगत 14 मई को बैठक लेकर सभी के बयान लिए थे। दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करने का समय देकर एक सप्ताह बाद मंगलवार को बैठक को कहा था। सूत्रों ने बताया कि पीजी डॉक्टरों में आपस में सुलह नहीं हो सकी है, फैकल्टी में भी गुटबाजी बरकरार है। यह मामला उच्च स्तर तक पहुंच सकता

चुनाव को देखते हुए हरियाणा ने रोका दिल्ली का पानी : आतिशी

दिल्ली आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली को मिलने वाला यमुना नदी का पानी रोका दिया है। दिल्ली सरकार ने मंत्री आतिशी ने इसे चुनावी साजिश बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस विषय पर हरियाणा सरकार को पत्र लिखेगी। जरूरत पड़ने पर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी (आतिशी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से जगह-जगह से पानी की शिकायत आनी शुरू हुई, खास तौर पर ऐसे इलाकों से जहां पहले कभी पानी की शिकायत नहीं आती थी। जांच करने पर पता लगा कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। आतिशी ने बताया कि वजीरबाद में यमुना का स्तर सामान्य तौर पर 674 फीट होता है। अपने न्यूनतम स्तर पर यह 672 फीट तक चला जाता है। 11 मई से 21 मई तक लगातार हरियाणा ने धीरे-धीरे दिल्ली का पानी रोका। 11 मई को यमुना में पानी का स्तर 671.6 फीट पर था। तीन दिन तक 671.6 फीट पर बना रहा। 14 और 15 मई को यह 671.9 फीट पर रहा। 16 मई को घटकर 671.3 फीट पर आया। 17, 18, 19 मई को यह और नीचे आ गया। यहां पानी का जलस्तर 671 फीट पर आ गया। 21 मई को 671 फीट के भी नीचे आ गया। फिर यह 670.9 फीट पर रह गया। आतिशी का कहना है कि यह शायद पहली बार है जब दिल्ली के वजीरबाद में यमुना जल स्तर इतना कम हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार 25 मई को दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है।

सभी तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

सुगम और सुविधाजनक यात्रा के लिए मुख्यमंत्री धामी गंभीर

देहरादून : प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिए जाने से अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। तीर्थयात्रियों की सुझा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा पर देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम और सुविधाजनक यात्रा को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा के लिए शासन प्रशासन के अधिकारियों से लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बुधवार को



मुख्य सचिव गधा रतूड़ी ने अनिवार्य पंजीकरण का आदेश जारी किया है। शासनादेश में तीर्थयात्रियों से कहा गया है कि पंजीकरण के बाद ही यात्रा पर जाएं। बिना पंजीकरण के आने पर उन्हें बैरियर या चेक प्वाइंट पर रोका जा सकता है। और ऐसा होने पर उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि पंजीकरण होने पर वे निर्धारित तिथि पर ही यात्रा पर जाएं। जिस

बुद्ध पूर्णिमा का स्नान, शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद

हरिद्वार। चारधाम यात्रा की भीड़ के बीच गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा का स्नान होगा। स्नान पर्व को लेकर तैयारियों को हरिद्वार पुलिस ने फाइनल टच दे दिया है। गुरुवार सुबह पांच बजे से स्नान पर्व के सकृशल सम्पन्न होने तक शहर क्षेत्र में भारी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारी वाहन को ही शहर क्षेत्र में एंट्री दी जाएगी। भीड़ का दबाव अधिक होने पर ही जिले में डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। बुधवार की शाम से ही पुलिस क्षेत्र में तैनात हो गई है।

स्टार्टअप के लिए सही माहौल मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : पीएम मोदी

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सरकार स्टार्टअप को फलने-फूलने के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को देश के हर हिस्से, खासकर टिबर -2 और 3 शहरों में युवाओं में भारी उर्जा पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार सत्रित रूप से स्टार्टअप और धन सृजन को प्रोत्साहित करती है।



इनोवेटर्स और टेक्नोप्रेटर्स ने कहा कि अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों को चलते भारतीय

अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में विशेष संपर्क अभियान कार्यक्रम में भाग लिया और केंद्रीय मंत्री हरीश्वर सिंह पुरी और राजीव चंद्रशेखर के साथ बातचीत की।

IHMS

KOTDWAR

"Journey Towards Excellence"

Institute of Hospitality, Management & Sciences

18 Years of Excellence in Education
ESTD. 2006
ISO 9001:2015 Certified

FREE LAPTOP

ADMISSIONS OPEN

PROGRAMMES AVAILABLE

M.B.A. 2 Years	M.C.A. 2 Years	B.H.M. 4 Years	B.C.A. 3 Years	B.Sc.IT. 3 Years	B.B.A. 3 Years	C.H.M. 1 Year
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------

OUR POTENTIAL RECRUITERS

